

कांग्रेस ने बिहार के चुनाव में सहायक की भूमिका निभाने की स्वीकृति दी

इससे पूर्व गांधी की सफल “वोट चोरी” यात्रा के बाद कांग्रेस में महत्वाकांक्षा जागी थी कि वह महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभायेगी

केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हुए

देहरादून, 23 अक्टूबर। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में बसे देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत, मां यमुनोत्री मंदिर और जनपद रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए गुरुवार को

- वैदिक मंत्रोच्चारण व सेना के वाद्य मंत्रों की धुनों के बीच भैया दूज के दिन कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई।

बन्द हो गए।

हिन्दू पंचांग गणना के अनुरूप भैया दूज, कार्तिक शुक्ल सप्तमी, अनुराधा नक्षत्र के पावन अवसर पर, वैदिक मंत्रोच्चारण और सेना के वाद्य यंत्रों की भक्तिपूर्ण मधुर धुनों के बीच इन दोनों पवित्र धामों के कपाट बंदी की प्रक्रिया संपन्न हुई।

पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस अवसर पर यमुनोत्री धाम से सम्बद्ध पंढा पुरोहितों, के अलावा, कुल 132 भक्त कपाट बन्द होने की प्रक्रिया के साक्षी रहे। यहां इस यात्रा वर्ष में कुल 6 लाख, 44 हजार 637 श्रद्धालुओं ने माता यमुना जी के दर्शन किए हैं। जबकि भगवान श्री केदार नाथ मंदिर में आज कुल 11,41,5 पंजीकृत श्रद्धालु कपाट क्रिया के दौरान उपस्थित रहे। अभी तक सम्पूर्ण यात्रा काल में यहां कुल 17 लाख 68 हजार 795 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होता है कि कांग्रेस ने फिलहाल अपनी महत्वाकांक्षाओं को स्थगित कर दिया है। जबकि कांग्रेस ने दो कदम पीछे हटाए हैं, वह चुनाव बाद के परिदृश्य में चार कदम आगे बढ़ने की उम्मीद करती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस संदर्भ में अप्रत्यक्ष संकेत दिए, यह कहते हुए कि विपक्षी खेमों को एक नेता या एक पार्टी नहीं चला रही है, बल्कि यह एक जैसे विचारों वाली पार्टियों और नेताओं का गठबंधन है। यह महत्वपूर्ण है कि जबकि मुकेश सहनी को संभावित डिप्टी मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है, वहीं गहलोत ने घोषणा की कि महागठबंधन की जीत की स्थिति में एक और डिप्टी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। संभावना है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार को दूसरा डिप्टी मुख्यमंत्री घोषित करने की कोशिश करेगी, जो संभवतः पिछड़ी जाति का उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि, यह गणना इस समय एक बड़ी आशा मात्र हो सकती है, क्योंकि यह देवना बाकी है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कांग्रेस गुट का मानना था कि, हालांकि, उसे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में दो कदम पीछे हटना पड़ा है, पर, चुनाव के बाद जो परिस्थितियाँ बनेंगी, उसमें वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में चार कदम आगे बढ़ जायेगी।

- विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी को उपमुख्यमंत्री पद का वादा करने के बाद, अब कांग्रेस का लक्ष्य है कि चुनाव के बाद अपने आदमी को दूसरा उपमुख्यमंत्री बनवा लेगी।

- राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस की यह आशा यथार्थ में तभी परिवर्तित होगी, जब उसका चुनाव में प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर होगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस सत्तर सीटों पर लड़ी थी और केवल उन्नीस सीटों पर जीती थी।

विधायक ही अगले मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला करेंगे।

आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तेजस्वी यादव के चेहरे वाले बैकग्राउंड पोस्टर पर यह कैप्शन था: बिहार मांगे तेजस्वी

सरकार। राहुल गांधी की सफल “वोट चोरी” यात्रा के बाद, राज्य कांग्रेस महागठबंधन में “बड़े भाई” की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह प्रतीत

प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ चिटनिस का निधन

नयी दिल्ली, 23 अक्टूबर। प्रख्यात भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चिटनिस का बुधवार को पुणे स्थित उनके आवास पर दिल का

- मृत्यु के समय उनकी आयु 100 वर्ष थी।

दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 1०० वर्ष के थे।

भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मशहूर चिटनिस ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (आईएनसीओएसपीएआर) की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के रूप में विकसित हुई।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर चिटनिस को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें, “हमारे अंतरिक्ष अभियान के प्रतीक पुरुषों में से एक” बताया है। रमेश ने 1० फरवरी, 1962 की उस ऐतिहासिक मुलाकात को याद किया, जब चिटनिस, इसरो के जनक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लालू प्रसाद और उनके बेटे और उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव से बातचीत करने के लिए बुधवार को पटना पहुँच गये थे।

गहलोत ने बुधवार को लालू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, “हम एनडीए का मुकाबला एक टीम के रूप में करेंगे। अगर 243 में से 5 या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिनों तक चली तकरार के बाद, जिसने उन्हें बिहार के कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है, दोनों दलों ने बुधवार को आपस में सामंजस्य बैठाने और ताकतवर से एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती से चुनावी लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजद प्रमुख

महागठबंधन के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी छाए, राहुल नदारद

पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। पटना में महागठबंधन की बहुप्रतीक्षित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थल पर लगे एक बैनर से इन्डिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की तस्वीरें गायब थीं, जिससे विवाद खड़ा हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस बैनर की तस्वीर पर केवल राजद नेता तेजस्वी यादव की एक बड़ी तस्वीर थी। महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य की राजधानी में आयोजित की गई थी।

इन्डिया ब्लॉक के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध के बीच, महागठबन्धन के नेताओं की यह पहली हो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव, बिहार चुनावों के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और अन्य नेता उपस्थित थे।

कांग्रेस और राजद के बीच कई

मनीष शर्मा युवा कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। कांग्रेस ने गुरुवार को कृष्णा अल्लावरू की जगह मनीष शर्मा को भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। अल्लावरू वर्तमान में पार्टी के बिहार

- वे कृष्णा अल्लावरू की जगह लेंगे अल्लावरू बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं।

प्रभारी हैं और पिछले कई महीनों से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे।

कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्त के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शर्मा की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस पार्टी ने यह बदलाव उस समय किया है, जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। मनीष शर्मा कांग्रेस के वाइट टी-शर्ट मूवमेंट का प्रभार देख रहे हैं। यह आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने कभी हाँ कभी ना की नीति त्यागी और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये

दो रूसी कंपनियाँ, जो रूस का पचास प्रतिशत से ज्यादा तेल निर्यात करती हैं, से तेल खरीदने वाले देशों को भारी दिक्कत में डाला

-अंजन राय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंततः रूस पर कड़ा प्रहार किया है। इसके पहले उसने कई बार रूस को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी और फिर इन प्रतिबंधों को लागू करने से बचता रहा।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के दो प्रमुख तेल निर्यातकों, लुकोइल और रोसनेफ्ट पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों का संयुक्त रूप से रूस के कुल तेल निर्यात में आधा हिस्सा है।

इन प्रतिबंधों के लागू होने के बाद, भारत के लिए रूस के तेल के आयात को जारी रखना कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। वैश्विक मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रूस के तेल का प्रमुख खरीदार थी, पहले ही वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

रूस से तेल खरीदने के बजाय, बड़े पैमाने पर ग्लोबल मार्केट से तेल खरीदना शुरू होने से वैश्विक तेल कीमतों में तेजी आ सकती है। हालांकि, भारत अपनी बड़ी खरीदारी के कारण कुछ छूट की मांग कर भी सकता है। तथापि, बदले हुए खरीद कार्यक्रम

- इन कंपनियों से जो तेल खरीदेंगे, उन्हें अमेरिका ब्लैकलिस्ट करेगा और जो बैंक यह सौदा करवाने की सुविधा प्रदान करेंगे उन्हें अमेरिका की मार्केट में काम नहीं करने दिया जायेगा और ये बैंक अमेरिका के क्लियरिंग हाउस सिस्टम का उपयोग भी नहीं कर पायेंगे।

- ट्रंप ने जबसे यह महसूस किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के साथ फायनैशियल समझौता करने को बारे में गंभीर नहीं हैं तथा अमेरिका के किसी भी शांति प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तभी से उन्होंने मन बनाया था कि वे रूस के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगायेंगे।

- उदाहरण के लिए, पुतिन ने यूक्रेन की 80-85 प्रतिशत भूमि पर अपने नियंत्रण की मांग रखी, इसमें वह क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर अभी यूक्रेन का पूर्ण कब्जा है।

- इन आर्थिक प्रतिबंधों को सफल बनाने में अमेरिका कितना गंभीर है, इस पर निर्भर करेगी, प्रतिबंधों की सफलता या असफलता।

वैश्विक बाजारों पर भारी दबाव बनाएंगे। तथापि, अब तक इस बात का कोई संकेत नहीं है कि चीन इन प्रतिबंधों से

प्रभावित हुआ है या नहीं। भारत के अलावा, चीन रूस के तेल का प्रमुख (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बॉलीवुड का सैट डिज़ायनर महागठबंधन का भावी उपमुख्यमंत्री कैसे बना

पटना के मौर्य होटल में सहनी ने नाटकीय ढंग से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की और महागठबंधन को घोषणा करने को मजबूर किया

- गठबंधन के सभी घटक नेताओं को वरिष्ठ पर्यवेक्षक के कमरे में इकट्ठा होकर संयुक्त महागठबंधन की बैठक में जाना था, एकता प्रदर्शित करते हुए।

- सभी नेता आए, पर, मुकेश सहनी नहीं आए, उन्होंने संदेश भिजवाया कि महागठबंधन यदि सामाजिक न्याय में विश्वास करता है तो मल्लाह समुदाय के प्रतिनिधि को उपमुख्यमंत्री का पद प्रेषित किया जाए।

- कांग्रेस नेताओं ने मजबूरन दिल्ली बात की। मल्लाह जाति का राजनीतिक महत्त्व समझते हुए दिल्ली से स्वीकृति दी और सहनी प्रैस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए।

अनुकूल हो। उन्होंने कथित तौर पर गठबंधन के नेताओं से कहा, “अगर ‘महागठबंधन’ सामाजिक न्याय की बात करता है, तो हम पदों में भी हिस्सेदारी चाहते हैं, सिर्फ सीटें नहीं।”

यह ड्रामा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने

से कुछ घंटे पहले हुआ।

सूत्रों के मुताबिक, सहनी मौयाँ होटल के एक सुइट में ठहरे हुए थे। विपक्षी गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता भी उसी होटल में ठहरे थे इनमें अशोक गहलोत भी थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सुइट संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नेताओं की बैठक का केंद्र था। तेजस्वी यादव ने समय पर पहुँचकर हिस्सा लिया, लेकिन मुकेश सहनी नहीं पहुँचे। संदेश स्पष्ट था – ‘अगर यादव को गठबंधन का चेहरा बनना है, तो मैं उनका डिप्टी बनूँगा।’

सहनी की घोषणा ने महागठबंधन में नाजुक सामंजस्य को खतरे में डाल दिया, जिसके कारण यादव को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा। राजद प्रमुख ने सहनी को आश्वासन दिया कि अगर विपक्षी गठबंधन चुनाव जीतता है, तो हर पार्टी को सरकार में हिस्सा मिलेगा। हालांकि यह आश्वासन सहनी के लिए पर्याप्त नहीं था।

फिर गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से बात की। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘गरीबों और बेघरों पर भारी पड़ेगी सर्दी’

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर। देश में हर साल सर्दी के मौसम में हजारों गरीब और बेघर लोगों को कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप झेलना पड़ता है। इस साल भी

- मानवाधिकार आयोग ने आशंका जताई और राज्य सरकारों के लिए अलर्ट जारी किया।

लाखों बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ठंड का कहर झेलना पड़ सकता है। इस संकट से गरीब बेघर परिवारों को बचाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सर्दी के मौसम में शीतलहर की संभावना को देखते हुए गुरुवार को देश के 19 राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों से गुजारिश की है कि वे आश्रय और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)